



प्रज्ञात समाचार

सच की आवाज, जनता के साथ

वर्ष: 1 अंक: 10

सोमवार, 27 जुलाई से 02 अगस्त 2026

पृष्ठ: 6

मूल्य: 2 रुपये

राहुल ने कहा- प्रधान को पद से हटाना ही होगा नरेन्द्र मोदी भारत का अतीत हैं, वे भविष्य से नहीं लड़ सकते

सरकार ने अपना हक मांग रहे मासूम छात्रों के खिलाफ हर संभव क्रूर कदम उठाए- मेट्रो बंद की, रास्ते बंद किए



लोक बंद नहीं कर पाए। राहुल बोले- धर्मद्र प्रधान क्रिमिनल शिक्षा मंत्री, इस्तीफा दें: अपने आवास 10 जनपथ पर छात्रों के प्रदर्शन में घायल एक स्टूडेंट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राहुल ने कहा, ह्मधर्म प्रधान एक अपराधी शिक्षा मंत्री हैं। वे हमारे एजुकेशन सिस्टम के ध्वस्त होने का प्रतीक हैं। उन्हें जाना ही होगा। उन्हीं की वजह से हजारों लोग सड़कों पर हैं। उन्होंने छात्र के हाथ, पीठ और छाती में लगे घाव को दिखाया। राहुल ने

कहा, मैं यह बताना चाहता हूँ कि यहां खड़ा मेरा भाई उस समय पैलेट गन से घायल हो गया था, जब वह तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध-प्रदर्शन कर रहा था। 20 जुलाई को नीट पेपर लोक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च निकाला था। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 100 से ज्यादा छात्र और पुलिसकर्मी घायल हुए थे। साहिल इनमें से एक है।

बोले राहुल, ब्रिटिश दौर के अत्याचारों को भी पार कर गई मोदी सरकार: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई में घायल हुए एक छात्र का वीडियो भी शेयर किया और आरोप लगाया कि अपने हक की मांग कर रहे निंदोष युवाओं के साथ मोदी सरकार का व्यवहार ब्रिटिश दौर के अत्याचारों की भी पार कर गया है।

नीट छात्रों के जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच बड़ी खबर आई है। छात्रों की मांग पर शिक्षा मंत्री धर्मद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया

प्रज्ञात समाचार

नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर नीट छात्र धरना प्रदर्शन दे रहे थे, उन्होंने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है।

मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूँ। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम

प्रज्ञात समाचार

नई दिल्ली। राहुल गांधी शनिवार सुबह 11:30 बजे अपने आवास 10 जनपथ के बाहर मीडिया से बातचीत करेंगे। इससे पहले राहुल ने शनिवार सुबह पर पोस्ट कर कहा, मोदी जी ने सब बंद कर दिया पर उनसे पेपर लोक बंद नहीं हुआ। उन्होंने लिखा कि सरकार ने अपना हक मांग रहे मासूम छात्रों के खिलाफ हर संभव क्रूर कदम उठाए- मेट्रो बंद की, रास्ते बंद किए, दुकानें बंद करवाई, इंटरनेट ठप किया और यहां तक कि खाना तक रकवा दिया। लेकिन मोदी जी, इतने जुल्म ढहाने के बाद भी आप पेपर

राम मंदिर दान चोरी पर एसआईटी इसी हफ्ते रॉप सकती है फाइनल रिपोर्ट

लखनऊ (प्रज्ञात समाचार)। अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी का खुलासा होने के तुरंत बाद गठित किए गए विशेष जांच दल की अंतिम (विस्तृत) रिपोर्ट लगभग तैयार है। जांच के दौरान आए तथ्यों, साक्ष्यों तथा बयानों की स्कूटी वल रही है, ताकि रिपोर्ट में किसी तरह की कमी न रहने पाए। एसआईटी ने स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की है। एसआईटी इसी हफ्ते अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। दूसरी रिपोर्ट दाखिल करने से पहले सभी तथ्यों पर दोबारा जांच चल रही है। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले विधि विशेषज्ञों से भी राय ली जाएगी। विस्तृत रिपोर्ट में आधारहीन आरोपों को शामिल नहीं किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अंतिम रिपोर्ट लगभग तैयार कर ली गई है। अब तथ्यों की दोबारा जांच की जा रही है ताकि हर सवाल के जवाब रिपोर्ट में शामिल रहें।

कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपके को हुआ टाइफाइड



दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन का शनिवार को 36वां दिन रहा

प्रज्ञात समाचार

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को टाइफाइड हो गया है। उन्होंने शनिवार को वीडियो जारी कर यह जानकारी दी। वहीं, दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार देर रात जंतर-मंतर पर बैरिकेडिंग बढ़ा दी है। शुक्रवार को

केंद्रीय मंत्रियों से बैठक के बाद सीजेपी ने कहा था कि अगर प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो 20 जुलाई जैसा एक्शन लेंगे। इस बीच, प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि अगर धर्मद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो सरकार से बातचीत का कोई मतलब नहीं है। शुक्रवार को सीजेपी ने दावा किया था कि सरकार ने आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस लेने पर सहमति दी है।

लालच, लापरवाही और लचर व्यवस्था ने दो की जान ले ली। पटाखा फैक्ट्री में मानक पूरे नहीं

प्रज्ञात समाचार

सहारनपुर। सहारनपुर के गंगोह के कूड़ाबसी गांव स्थित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की तीन बड़ी वजह सामने आई है। घटनास्थल पर जिस तरह चार कमरों में विस्फोटक सामग्री और पटाखे रखे हुए थे उससे लग रहा है कि वहां पर क्षमता से अधिक भंडारण था। लाइसेंस केवल 15 किग्रा का था। दूसरी वजह है कि फैक्ट्री के लिए लाइसेंस जरूर था, लेकिन इसके अलावा कोई अन्य मानक पूरा नहीं था। तीसरी और सबसे अहम वजह है प्रशासनिक अनदेखी।

पहली वजह: फैक्ट्री करीब पांच साल पहले शुरू हुई थी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि फैक्ट्री के पास 2028 तक का लाइसेंस है। जानकारी करने पर पता चला कि लाइसेंस 15 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री के लिए लाइसेंस लिया गया था, लेकिन फैक्ट्री में चार कमरे हैं और चारों में विस्फोट सामग्री



मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखता हूँ...

मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूँ तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूँ। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं हैं, बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निमाता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुःखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिका का विषय नहीं है। भारत की युवाशक्ति ही, इस देश की असली ताकत है। देश की युवाशक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसे नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है।

सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर

मुझे प्राप्त हुआ उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट

पटाखा फैक्ट्री में धमाका: लाइसेंस था 15 किग्रा का हर कमरे में दिखा बारूद, सामने आई विस्फोट की ये तीन बड़ी वजह



और पटाखे रखे हुए थे। कुछ पटाखे बाहर धूप में सूखने के लिए भी रखे गए थे। वह 15 किलोग्राम से कहीं ज्यादा थे। आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि फैक्ट्री में पिछले कुछ दिनों से हलचल बढ़ गई थी।

दूसरी वजह: नियमानुसार, फैक्ट्री शहर या आबादी वाली जगहों से दूर और खुले खेतों या औद्योगिक क्षेत्र में होनी चाहिए, लेकिन यह फैक्ट्री गांव से मात्र 300 मीटर दूर है। इमारतों में ऐसी सामग्री का इस्तेमाल होना चाहिए, जो चिंगारी न छोड़े। फर्श पर एंटी-स्टैटिक रबर मैट होने जरूरी हैं, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं दिखा। केवल सामान्य कमरे बनाए गए थे। आग बुझाने के यंत्र, पानी की टंकी, रेत की बोरियां और फायर अलार्म सिस्टम हर समय

तैयार हालात में होने चाहिए, लेकिन यहां पर अग्निशमन यंत्र के नाम पर केवल एक उपकरण दिखाई दिया। इसके अलावा सबसे अहम है कि मजदूरों की आग से बचाने वाले सूती कपड़े, सेफ्टी गॉगल्स और विशेष जूते होने चाहिए। तीसरी वजह: तीसरी वजह प्रशासनिक अनदेखी सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब डेढ़ साल पहले भी फैक्ट्री में आग लगी थी। हालांकि उसमें कोई जनहानि नहीं हुई थी। मामले को रफा दफा कर दिया गया था। अगर अधिकारियों ने गंभीरता दिखाई होती तो शायद यह हादसा नहीं होता। एनसीआर से बाहर होने की वजह से जिले में पटाखा फैक्ट्री की संख्या काफी है।

ट्रम्प बोले- चीन-रूस जंग में आए तो अंजाम बुरा होगा



पुतिन-जिनपिंग ने मुझे यकीन दिलाया, वे ईरान को हथियार नहीं देंगे

प्रज्ञात समाचार

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें नहीं लगता कि चीन या रूस ईरान युद्ध में शामिल हैं। हालांकि उन्होंने धमकी दी कि अगर दोनों देशों ने इस युद्ध में दखल दिया तो इसके गंभीर नतीजे होंगे और यह उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हाल ही में बीजिंग में हुई उनकी मुलाकात के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिया था कि वे किसी भी हाल में ईरान को हथियार नहीं देंगे। चीनी कंपनियों के लिए भी यही चीज लागू है।

ट्रम्प ने कहा मुझे जिनपिंग पर

यकीन है। उन्होंने यह भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी उनसे कहा था कि वे ईरान को हथियार नहीं देंगे। ट्रम्प ने कहा कि यूक्रेन जंग के बावजूद उनकी पुतिन से बातचीत जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका सीधे यूक्रेन को हथियार नहीं बेचना, बल्कि नाटो देशों को बेचना है। नाटो देश इन हथियारों की पूरी कीमत चुकाते हैं। उसके बाद वे इन्हें किस तरह आगे भेजते हैं, इसकी उन्हें जानकारी नहीं होती।

नेतन्याहू अमेरिका जाएंगे, जंग के बाद पहली बार ट्रम्प से मुलाकात: इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को कि वे किसी भी हाल में ईरान को हथियार नहीं देंगे। चीनी कंपनियों के लिए भी यही चीज लागू है।

दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का टेस्ट कामयाब

पानी में पहली बार सुरक्षित लैंडिंग, अंतरिक्ष में 20 सेटेलाइट भी तैनात किए, मस्क की कंपनी का मिशन



प्रज्ञात समाचार नई दिल्ली। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप की 13वीं टेस्ट उड़ान कामयाब रही। इस मिशन में स्टारशिप के अपर स्टेज ने हिंद महासागर में लैंड

किया, जबकि इसके बुस्टर ने मैक्सिको की खाड़ी में लैंडिंग की। पिछले हफ्ते इंजन इमिशन में खराबी के कारण इसकी लॉन्चिंग टाल दी गई थी। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलॉन मस्क की

कंपनी स्पेसएक्स ने इस रॉकेट को बनाया है। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट (ऊपरी हिस्सा) और सुपर हैवी बुस्टर (निचला हिस्सा) को कलेक्टिवली 'स्टारशिप' कहा जाता है। इस व्हीकल की ऊंचाई 403 फीट है। ये पूरी तरह से रीयूजेबल है। स्टारशिप ने टेक्सास के दक्षिणी छोर पर स्थित ह्वास्टरबेसड से भारतीय समय के अनुसार सुबह करीब 4 बजे उड़ान भरी थी। ये टेस्ट 1 घंटे 3 मिनट का था।

गाजियाबाद में 20 करोड़ के जेवर चोरी का दावा



परिवार प्रयागराज गया था, चोर भगवान का सोने का सिंहासन भी ले गए

प्रज्ञात समाचार

लोनी। गाजियाबाद के अंकुर विहार थाना क्षेत्र की डीएलएफ कॉलोनी में एक घर में करीब 20 करोड़ रुपये के जेवरात और अन्य कीमती सामान चोरी होने का दावा सामने आया है। घटना उस समय हुई, जब परिवार प्रयागराज में दिवंगत सदस्य की बरसी में शामिल होने गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शुरूआती जांच में पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है।

पोंडिता भूमिका द्विवेदी अशक ने पुलिस को बताया कि वह अपने दिवंगत पति नीलाध अशक की बरसी में शामिल होने प्रयागराज गई थी। 24 जुलाई की सुबह करीब आठ बजे जब वह घर लौटीं तो सभी दरवाजे अंदर से बंद मिले। अनहोनी की आशंका होने पर उन्होंने तुरंत डायल-112 पर सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया। अंदर दराज टूटे मिले, जबकि सामान पूरे घर में बिखरा पड़ा था। शिकायत के अनुसार, चोर हरि, नीलम, पन्ना, माणिक समेत बहुमूल्य रत्न और उनसे बने आभूषण अपने साथ ले गए।

पूजा घर से सोने का सिंहासन भी ले गए: पोंडिता का कहना है कि चोर पूजा घर में रखा भगवान का सोने का सिंहासन और सोने-चांदी की मूर्तियां भी चोरी कर ले गए।

सीएम योगी ने फतेहपुर में 487 करोड़ की योजनाएं समर्पित कीं। 'सैफई सिंडिकेट' पर हमला, विकास निधि के दुरुपयोग का आरोप। नीट पेपर लोक पर सख्त कार्रवाई, 47 एनटीए अधिकारी बर्खास्त।

प्रज्ञात समाचार

फतेहपुर। फतेहपुर के मदारीपुर कला में मुख्यमंत्री सीएम ने 487 करोड़ की लागत वाली योजनाओं का लोकार्पण बटन दबाकर मंच स्थल से किया। मंच से मुख्यमंत्री ने भीड़ का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। सीएम ने अपने संबोधन में विकास और रोजगार की बात कही।

सीएम योगी ने कहा कि स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को एक साथ फांसी के फंदे पर चढ़ना गया।



ठाकुर दरियाव सिंह उनके वीर पुत्र सुजान सिंह अमर शहीद जोधा सिंह को जन्म दिया और जिसे धारा के निर्भीक पत्रकार के रूप में गणेश शंकर विद्यार्थी और राष्ट्रकवि सोहनलाल पैदा हुए। इस पावन धरा को काफी दिनों के बाद आपके जनपद में आने का सीमाव्य प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि बाबा की धरती 2017 के पहले आकांक्षी जनपद था। काशी जनपद का मतलब कृषि विकास रोजगार विकास अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। जो पैरामीटर देश के

अंदर तय किए गए थे, उसमें सबसे पिछड़े हुए जनपदों में फतेहपुर की गिनती होती थी, क्योंकि यहां का विकास का पैसा सैफई सिंडिकेट के द्वारा लूट लिया जाता था। फतेहपुर की योजना को वहां पर सैफई के अंदर नाच-गानों में खर्च कर दिया जाता था।

आज फतेहपुर के नौजवान नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हैं तो अच्छा लगता है: सीएम ने कहा कि आज मैं देखता हूँ यूपी के अंदर कोई नौकरी का नियुक्ति पत्र वितरण करता हूँ, यूपी पुलिस, शिक्षकों की भर्ती, सेवा चयन आयोग के माध्यम से अभियंताओं की भर्ती हो या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस

कमीशन के माध्यम से होने वाली कोई भी नियुक्ति। मुझे फतेहपुर के नौजवान दिखाई देते और फतेहपुर के नौजवान भी बड़े गर्व के साथ अपनी योग्यता के अनुसार नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है।

नीट पर बोले सीएम योगी: सीएम योगी ने फतेहपुर से कहा कि नीट में जिन माफिया ने पेपर लोक किया उनकी कड़ी सजा मिलनी शुरू हो गई है। एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त किए गए हैं। सीएम बोले कि मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूँ यह डबल इंजन की सरकार है। जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया ता मान कर चलिए कि उसे मिट्टी में मिला देंगे। यूपी में नौ लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी दी। सपा सरकार में बेटी, बहन और व्यापारी घबराए हुए थे। अब सब सुरक्षित हैं। सीएम ने कहा कि अच्छी सरकार आती है तो बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ती है।

छात्रों में असंतोष या विपक्ष का सियासी दांव?

संसद के मानसून सत्र के दौरान राष्ट्र की सर्वोच्च पंचायत संसद केवल विधायी बहसों या नीतिगत बहसों का केंद्र नहीं रही, बल्कि यह देश के लाखों युवाओं के भविष्य, आक्रोश और असंतोष का रणक्षेत्र बन गई है। संसद के मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही व्यवधान उत्पन्न होता नजर आ रहा है। गया। विपक्षी दलों के सांसदों के इस मामले को लेकर कड़े तैवर हैं और सरकार के खिलाफ अलग अलग रूप में आंदोलन चलाने पर उतारू हैं यानी पूरे देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। इस पूरे बवाल के मूल में नीट (नेशनल एलिजिविलिटी कम एट्रेंस टेस्ट) परीक्षा में कथित धांधली, पेपर लीक के आरोप, और राजधानी दिल्ली में लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों तथा युवाओं पर पुलिस द्वारा किया गया बल प्रयोग है। विपक्ष अब सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ गया है। सड़कों पर शुरू हुआ एक शैक्ष-णिगक आंदोलन अब देश का सबसे बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है, जिसने संसद में सरकार के विधायी एजेंडे पर गंभीर दबाव बना दिया है। भारत जैसे जीवंत और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब देश का युवा सड़कों पर उतर आए और संसद की कार्यवाही ठप हो जाए तो यह पूरी व्यवस्था के लिए चिंतन का विषय है। संसद का काम केवल कानून बनाना नहीं, बल्कि देश के नागरिकों, विशेषकर युवाओं के संशय और पीड़ा का समाधान करना भी है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह विपक्ष और प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ एक पारदर्शी संवाद कायम करे, ताकि जांच पर विश्वास जहाल हो सके। वहीं, विपक्ष को भी चाहिए कि वह विधायी कामकाज में भागीदारी करते हुए संसद को ही अपनी बात और तर्कों का सबसे मजबूत मंच बनाए। यदि समय रहते इस गतिरोध और युवा असंतोष को तार्किक परिणति तक नहीं पहुंचाया गया, तो इसका नुकसान केवल राजनीति को नहीं, बल्कि भारत के उज्ज्वल भविष्य उसके युवाओं को भुगतना पड़ेगा। विपक्ष को नीट और छात्र असंतोष के रूप में एक ऐसा सर्वव्यापी मुद्दा मिल गया है जो सीधे देश के हर दूसरे-तीसरे परिवार को प्रभावित करता है। विपक्षी दल इसे आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए भी एक बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में विकसित कर रहे हैं। संसद के भीतर और बाहर विपक्ष ने इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, वामपंथी दलों, तृणमूल कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शायद विपक्ष का सबसे बड़ा हमला केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पर है। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि जब देश की सबसे बड़ी और संवेदनशील चिकित्सा प्रवेश परीक्षा की साख तार-तार हो गई है, तो मंत्री अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। विपक्ष का कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री पद पर बने रहेंगे, तब तक किसी भी जांच की निष्पक्षता पर संवाल उठने रहेंगे। कांग्रेस सांसदों ने तो यहां तक आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश के मेधावी छात्रों की आवाज सुनने के बजाय पुलिस की लाठियों से उसे दबाना चाहती है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर एक तरफ तो चर्चा का कर रहे हैं, वहीं सरकार इसके लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष संसद के भीतर हंगामा व नारेबाजी करके कार्यवाही को चलने नहीं दे रहे हैं। शायद विपक्षी दल इस मुद्दे पर अपनी सियासी रणनीति को मजबूत करना चाहता है। विपक्ष का दावा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) पूरी तरह से विफल साबित हो चुकी है और इसके शीर्ष अधिकारियों की जवाबदेही तय किए बिना केवल छोटे कर्मचारियों पर गाज गिराना अन्याय है। संसद और सड़कों पर विपक्ष के लगातार जारी आक्रामक तैवरों और हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने भी अपना रुख साफ किया है। सरकार का कहना है कि वह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बार-बार सदन में दोहराया कि सरकार नियम के तहत नीट मामले समेत किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर प्रश्नकाल के बाद निश्चित चर्चा कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार का आरोप है कि विपक्ष चर्चा करने के बजाय केवल सदन को ठप करने की राजनीति कर रहा है। सरकार का तर्क है कि पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए नया और कठोर ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम’ लागू किया जा चुका है। उच्च स्तरीय जांच एजेंसियां हर पहलू की गहनता से पड़ताल कर रही हैं। सरकार का कहना है कि बिना ठोस तथ्यों के पूरी परीक्षा को अचानक रद्द कर देना या जल्दबाजी में कोई फैसला लेना उन लाखों ईमानदार और मेधावी छात्रों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने वर्षों तक दिन-रात मेहनत की है। नीट विवाद और जंतर-मंतर पर हुई पुलिस कार्रवाई के बाद देश के माहौल में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। यह मामला अब केवल एक प्रतियोगी परीक्षा तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसके कई सामाजिक और राजनीतिक आयाम सामने आ चुके हैं। युवाओं में गहराता अविश्वास सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। बार-बार लीक होते पेपरों और प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी से देश के मध्यमवर्गीय और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं का भरोसा भारत की चयन और परीक्षा प्रणालियों से डगमगा रहा है। यह अविश्वास देश के जनसांख्यिकी लाभार्थ के लिए एक गंभीर चेतावनी है।

कटाक्ष | सुनेज मिश्र

मइया सोनम वांगचुक, धर्म करो कुछ यार
साथ तुम्हारे खड़े हैं, सबके सब गद्दार
सबके सब गद्दार, जगत को क्यों भरमाते
इससे अट्ठा यार, मुक्त धरती कर जाते
कह सुरेश जिसके लद्दाख डुबोया दइया
उनके साथ खड़े हो फिर से सोनम मइया

पीएम आवास पर राहुल गांधी का धरना प्रदर्शन अनैतिक

प्रधानमंत्री आवास देश का एक अति संवेदनशील, सुरक्षित और महत्वपूर्ण स्थान है, जो देश की प्रतिष्ठा, प्रभाव और प्रताप से जुड़ा है जो देश की एक सौ चालीस करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने का केंद्र है भले ही प्रधानमंत्री किसी भी राजनैतिक दल का हो। प्रधान मंत्री का आवास कोई धरना प्रदर्शन की जगह नहीं है।

जिस इंडि गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक कांग्रेस सहित अन्य दल अपने बलबूते अब तक सरकार के विरुद्ध देश में, अब तक कोई जन आंदोलन नहीं चला सके, वे देश के लिए एक अज्ञात, अपरिचित और अजनबी कॉंकरोच जनता पार्टी के आवाहन पर बीते 21 जुलाई 2026 को उनके आंदोलन के समर्थन में शामिल हुए। राहुल गांधी ने तो अपने को अलग दिखलाने की चाह में सारे नियम कानून और शिष्टाचार को ताक पर रख कर अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जहां सामान्य तो क्या असाधारण स्थितियों या परिस्थितियों में भी इस तरह के प्रदर्शन की किसी को अनुमति नहीं है। प्रधानमंत्री आवास देश का एक अति संवेदनशील, सुरक्षित और महत्वपूर्ण स्थान है जो देश की प्रतिष्ठा, प्रभाव और प्रताप से जुड़ा है जो देश की एक सौ चालीस करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने का केंद्र है भले ही प्रधानमंत्री किसी भी राजनैतिक दल का हो। प्रधान मंत्री का आवास कोई धरना प्रदर्शन की जगह नहीं है जहां आप सभी लोगों को सार्वजनिक तौर पर धरना-प्रदर्शन में शामिल होने का आवाहन करें? देश को पहले ही इसी सुरक्षा चूक के कारण दो-दो प्रधानमंत्रियों के बलिदान हो चुका है जहां प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा को संकट में डालने के राहुल गांधी के धरना प्रदर्शन के इस अपरिपक्व, अनैतिक और अदृग्दर्शी निर्णय की जितनी भी निंदा और भत्सना की जाय, कम है। यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष के प्रति आदर और सम्मान का भाव प्रकट करते हुए सरकार ने अपने एक केंद्रीय मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह को विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात कर इस संवेदनशील स्थल से धरना समाप्त करवाएं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बातचीत में राहुल गांधी ने संसद में आंदोलन और नीट (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) पर संसद में चर्चा कराने की एक मात्र मांग की। मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय माध्यम से बातचीत कर इस संसंध में सरकार की सहमति प्रदान कर दी। जब इस निर्णय से राहुल गांधी को अवगत कराया तो उन्होंने अपनी बात से पलटते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की



मांग जोड़ दी। जब राहुल गांधी से उनके अपनी बात से पलटने की याद दिलाई गयी तो उनका जवाब था कि "मेरी मर्जी"! मैंने पहले संसद में चर्चा की मांग की थी, अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी जोड़ दी। कांग्रेस के एक सांसद और नेता प्रतिपक्ष जैसे जिम्मेदार व्यक्ति से ऐसे गैरजिम्मेदार व्यवहार की अपेक्षा कदापि नहीं की जा सकती। यही नहीं, मंत्री महोदय और गृह मंत्रालय के सचिव ने जब राहुल गांधी का ध्यान प्रधानमंत्री आवास जैसे संवेदनशील स्थल पर धरना-प्रदर्शन के निषेध की याद दिलाई तो उन्होंने बड़ी ही हठधर्मिता से वहीं पर धरना देने की "मेरी मर्जी" से अवगत कराया। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास के इस धरना प्रदर्शन पर साथ देने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता भी थे। जब कांग्रेस और समाजवादी सहित अन्य राजनैतिक दलों ने पीएम आवास पर आंदोलन समाप्त करने के लिए पुलिस बल को बुलाया पड़ा। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने राजनैतिक शिष्टाचार दिखाते हुए पुलिस के आग्रह को स्वीकारते हुए अपनी गिरफ्तारी दे दी पर राहुल गांधी अखिलेश यादव का अनुरोध ठुकराते हुए, धरना स्थल पर लेट गए ताकि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो कि पुलिस बलों को राहुल गांधी को बलपूर्वक घटना स्थल से हटाने के लिए बाध्य

होना पड़े। अपने इस मकसद में वे बहुत हद तक कामयाब भी हुए। राहुल गांधी का अनुसरण उनकी सांसद बहिन प्रियंका गांधी ने भी किया। पुलिस बल को असहज स्थिति का सामना करते हुए नेता प्रतिपक्ष के सम्मान का ध्यान रखते हुए न्यूनतम बल का प्रयोग किया और उनको उठाकर बस में जबर्दस्ती बैठा कर गिरफ्तार करना पड़ा। एक छुटपने राजनैतिक कार्यकर्ता द्वारा लोगों की निगाह में आने, गिरफ्तारी के पूर्व हाथ पैर पटककर नाटक नौटंकी करना तो उचित प्रतीत होता पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद और नेता प्रतिपक्ष का ऐसा आचरण सामान्य शिष्टाचार और नैतिक मर्यादाओं के सर्वथा विपरीत था जिसने नेता प्रतिपक्ष जिसे गरिमा पूर्ण पद की प्रतिष्ठा को धूमिल ही किया। भारतीय राजनीति का खोखलापन इस आंदोलन में स्पष्ट दिखालाई दिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना, आप और एनसीपी जैसी स्थापित पार्टियां भी मोदी सरकार के विरुद्ध पिछले बाहर साल में कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा नहीं कर सकी, वहीं कॉंकरोच जनता पार्टी जैसी नवजात पार्टी ने अपने अस्तित्व के बाद सभी विरोधी दलों को अपना पिछलग्गू बना दिया। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के धुरंधर नेतागण भी कॉंकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके जैसे अनजान, अपरिचित और अज्ञात नेता के दरबार में हाजिरी लगाने को मजबूर हैं। ऐसा प्रतीत होता

है कि राहुल गांधी एक के बाद एक मिली असफलताओं के कारण हीन भावना से ग्रसित होकर एक अनाम, गुमनाम और बेनाम कॉंकरोच जनता पार्टी जैसे दल के मंच पर जाकर आंदोलन, धरना प्रदर्शन की सफलता का श्रेय कॉंकरोच पार्टी को न देकर इस आंदोलन का श्रेय स्वयं लेने के लोभ से वंचित नहीं रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जंतर मंतर के जगह पीएम आवास पर धरना देने के स्वार्थ पूर्ण निर्णय लेकर न केवल पीएम आवास की सुरक्षा को संकट में डाला अपितु अपनी अधम राजनैतिक स्वार्थपरता, अवसरवादिता और खुदगर्जी का परिचय दिया जो निन्दनीय है। ऐसा नहीं था कि एनईईटी पेपर लीक की घटना कोई पहली अनौचित्य घटना थी। कांग्रेस शासित राशस्थान में अशोक गल्लत सरकार के कार्यकाल में 17 पेपर लीक की घटनाएं हुईं, जिनमें सब इस्पेक्टर परीक्षा, जेईएन परीक्षा 2021, आरईईटी परीक्षा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा प्रमुख हैं। कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में भी जेओए-आईटी परीक्षा 2022, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022, सीपीएमटी परीक्षा 2006 के पेपर भी लीक हुए थे। तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में भी पेपर लीक की घटनाएं देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सपा सरकार के कार्यकाल में भी एक जाति विशेष के लोगों की बहुतायत में भर्ती की अनियमितताएं हुईं। लेकिन इन सरकारों ने भी अपने स्तर पर कड़ी कानूनी कार्रवाही कर अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी। एनईईटी परीक्षा के भी 13 अपराधियों को गिरफ्तार कर सरकार ने कड़ी कार्यवाही की है। लोक परीक्षा को निरस्त कर चुनाव परीक्षा कराई गयी ताकि परीक्षार्थियों को न्याय मिल सकें और ऐसा हुआ भी। योग्य अभ्यर्थियों का चयन द्वारा की की गयी परीक्षा में किया गया। कल प्रधानमंत्री ने भी मंगलवार 21 जुलाई 2026 को पुनः एनडीए संसदीय दल की बैठक में अपनी बस प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया कि नीट पेपर लीक के दावियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके विरुद्ध मिसाल कायम करने वाली सख्त कार्यवाही की जाएगी।

■ विजय सहगल

धर्म परिवर्तन की पैरवी करता धर्मनिरपेक्ष राज्य?

भारत का संविधान राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। इसका आशय यह है कि शासन का आधार किसी धर्म विशेष की मान्यताएं नहीं, बल्कि संविधान और विधि का शासन होना चाहिए। ऐसे में जब मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले जिसमें इस्लाम धर्म अपनाने वाला व्यक्ति पिछड़े वर्ग के मुस्लिम का दर्जा प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता। तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय सरकार ने इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय लिया तो इसने धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और पहचान-आधारित राजनीति पर एक नई बहस को जन्म दे दिया। भारतीय राजनीति में दशकों तक कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाता रहा है। समान नागरिक संहिता, शाह बानो प्रकरण, वस्त्र, पर्सनल लॉ और अल्पसंख्यक नीतियों को लेकर यह विमर्श लगातार चलता रहा किंतु अब यह बहस केवल कांग्रेस तक सीमित नहीं रह गई है। तमिलनाडु में पहली बार सत्ता में आई तमिलनाा वेत्री कड़गम सरकार का सर्वोच्च न्यायालय जाने का निर्णय भी उसी बहस को नया आयाम देता दिखाई देता है। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग स्वयं को भारतीय संविधान, लोकतंत्र और मुसलमानों के अधिकारों की पक्षधर पार्टी बताती है। दूसरी ओर, उसके आलोचक विभाजन-पूर्व ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था, की ऐतिहासिक विरासत का हवाला देते हुए उसकी धर्मनिरपेक्ष विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाते रहे हैं। यद्यपि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का दावा है कि स्वतंत्रता के बाद उसका राजनीतिक चरित्र पूरी तरह संवैधानिक और लोकतांत्रिक है, फिर भी उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समय-समय पर राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनती रही है। राज्य में 69 प्रतिशत आरक्षण लागू है, जो देश में सर्वाधिक है। विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब तमिलनाडु सरकार ने 2024 में एक सरकारी आदेश जारी कर यह व्यवस्था की कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, विमुक्त समुदाय तथा अनुसूचित जाति पृष्ठभूमि से इस्लाम स्वीकार करने वाले व्यक्तियों को पिछड़ा वर्ग- मुस्लिम प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है। जून 2026 में मद्रास उच्च न्यायालय ने इस सरकारी आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि केवल धर्म परिवर्तन किसी व्यक्ति को स्वतः अधिसूचित पिछड़े मुस्लिम समुदाय का सदस्य नहीं बना देता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पिछड़ा वर्ग का दर्जा केवल धार्मिक पहचान से नहीं, बल्कि वैश्विक रूप से अधिसूचित सामाजिक समूह की सदस्यता पर आधारित है। इसके बाद मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय लिया। सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है, जबकि आलोचकों का आरोप है कि यह कदम संवैधानिक सिद्धांतों से अधिक राजनीतिक संदेश देता है। निस्संदेह, किसी भी राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का संवैधानिक अधिकार है किंतु लोकतंत्र में केवल संवैधानिक वैधता पर्याप्त नहीं होती; राजनीतिक निर्णयों की नैतिक और वैचारिक समीक्षा भी होती है।

■ साभार

लोकतंत्र में टकराव नहीं, संवाद ही समाधान

देश की राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर हुए धरना-प्रदर्शन, उस दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज, उसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास की ओर किए गए विरोध मार्च तथा उसके प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा देशभर में कांग्रेस कार्यालयों के बाहर आयोजित प्रदर्शनों ने भारतीय राजनीति को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां लोकतांत्रिक असहमति और राजनीतिक टकराव के बीच की रेखा लगातार धुंधली होती दिखाई दे रही है। कई शहरों में हुई झड़पें और हिंसक घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अब सड़क पर शक्ति प्रदर्शन में बदलती जा रही है। इतिहास बताता है कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता बल्कि संवाद, सहिष्णुता और संस्थाओं के प्रति सम्मान से संचालित होता है। जब विरोध को केवल शक्ति से दबाने और जवाब में प्रतिरोध की ओर अधिक आक्रामक बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तब लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होने लगती है। यही कारण है कि वर्तमान घटनाक्रम को देखकर अनेक लोगों को वर्ष 1974 का दौर याद आने लगा है। 1974 का भारत भी राजनीतिक असंतोष, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के आरोपों और सरकार तथा विपक्ष के बीच गहरे अविश्वास का दौर था। छात्र आंदोलनों से शुरू हुई असंतुष्टि ने व्यापक जन आंदोलन का रूप लिया। राजनीतिक ध्रुवीकरण इतना बढ़ा कि अंततः देश ने आपातकाल जैसी असाधारण परिस्थिति का सामना किया। इतिहास कभी स्वयं को हूबहू नहीं दोहराता लेकिन उससे मिलने वाली चेतावनियों की अनदेखी भी नहीं



की जा सकती। आज का भारत निश्चित रूप से 1974 वाला भारत नहीं है। संस्थाएं अधिक विकसित हैं, मीडिया का स्वरूप बदल चुका है और डिजिटल माध्यमों ने सूचना के प्रवाह को अत्यंत तेज बना दिया है लेकिन यही डिजिटल माध्यम अफवाहों, उजेकत संदेशों और राजनीतिक ध्रुवीकरण को भी कई गुना बढ़ा देते हैं। परिणामस्वरूप किसी भी राजनीतिक घटना का प्रभाव कुछ ही घंटों में पूरे देश में दिखाई देने लगता है। यदि विरोध-प्रदर्शन लगातार हिंसक रूप लेते हैं, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव सामान्य बात बन जाती है तथा राजनीतिक दल एक-दूसरे के कार्यालयों, सभाओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने लगते हैं, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान लोकतंत्र को होगा। लोकतंत्र का अर्थ प्रतिद्वंद्वी का अस्तित्व समाप्त करना नहीं, बल्कि उसके विचारों से लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला करना है। सरकार के लिए भी यह स्थिति अनुकूल नहीं कही जा सकती। कानून-व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है लेकिन यदि बार-बार बल प्रयोग की तस्वीरें सामने आती हैं तो विपक्ष को सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन

का आरोप लगाने का अवसर मिलता है। दूसरी ओर, यदि हिंसक घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाता, तो सरकार की प्रशासनिक क्षमता पर भी प्रश्न उठते हैं। इसलिए सरकार के सामने संतुलित, संयमित और संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाने की चुनौती है। विपक्ष के लिए भी यह समय आत्ममंथन का है। लोकतांत्रिक विरोध प्रत्येक राजनीतिक दल का अधिकार है किंतु यदि आंदोलन हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति की क्षति या टकराव में बदल जाए तो उसका नैतिक आधार कमजोर पड़ जाता है। विपक्ष की सबसे बड़ी शक्ति जनता का विश्वास होता है और वह केवल शांतिपूर्ण एवं रचनात्मक राजनीति से ही अर्जित किया जा सकता है। इन सबसे अधिक नुकसान आम नागरिक को उठाना पड़ता है। सड़कें बंद होती हैं, यातायात प्रभावित होता है, व्यापार ठप पड़ता है, दैनिक मजदूरी करने वालों की आय रुक जाती है, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है और निवेश का वातावरण भी प्रभावित होता है। राजनीतिक दल अंततः अपने आप की तैयारी में लग जाते हैं लेकिन आम आदमी को रोजमर्रा की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी ऐसे

घटनाक्रमों से प्रभावित हो सकती है। दुनिया भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में देखती है। यदि लगातार राजनीतिक हिंसा, सड़क संघर्ष और संस्थागत टकराव की तस्वीरें सामने आती हैं, तो विदेशी निवेशकों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और वैश्विक समुदाय के बीच भारत की लोकतांत्रिक परिपक्वता पर अनावश्यक प्रश्न खड़े हो सकते हैं। हालांकि किसी भी लोकतंत्र में विरोध और आंदोलन स्वाभाविक हैं, किंतु उनका शांतिपूर्ण और संवैधानिक होना ही लोकतंत्र की वास्तविक पहचान है। इन परिस्थितियों के मूल कारणों पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। राजनीतिक दलों के बीच संवाद का लाभग समाप्त हो जाना, चुनावी राजनीति का अत्यधिक आक्रामक स्वरूप, सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ता वैचारिक ध्रुवीकरण, हर मुद्दे को राजनीतिक लाभ-हानि के चरम से देखने की प्रवृत्ति तथा सार्वजनिक विमर्श में संयम की कमी ऐसे प्रमुख कारण हैं जिन्होंने वातावरण को अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। जब संघर्ष और विधानसभाओं में संवाद कम होता है, तब सड़कें राजनीतिक संघर्ष का मुख्य मंच बन जाती हैं। मेरा आकलन है कि भारत अभी भी उस स्थिति से बच सकता है जिसकी आशंका कुछ लोग 1974 से जोड़कर व्यक्त कर रहे हैं। इसके लिए सरकार, विपक्ष, प्रशासन, मीडिया और नागरिक समाज—सभी को अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकार को असहमति को लोकतांत्रिक अधिकार मानते हुए कानून का नियंत्रण पालन सुनिश्चित करना चाहिए। विश्व को शांतिपूर्ण आंदोलनों की परंपरा को मजबूत करना चाहिए।

■ साभार

क्या भाजपा अपना अभेद्य किला बचा पाएगी?

। आज का काटून

साभार



बिहार की राजनीति में कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनके परिणाम केवल एक विधायक का चुनाव तय नहीं करते बल्कि राज्य की राजनीतिक दिशा और दलों की मनेवैज्ञानिक बहूत का संकेत भी देते हैं। पटना का बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र ऐसी ही सीट है। 30 जुलाई को होने वाला उपचुनाव केवल रिक्त सीट भरने का संवैधानिक अभ्यास नहीं है; यह भाजपा के संगठन, जन सुराज की राजनीतिक विश्वसनीयता और राष्ट्रीय जनता दल की शहरी राजनीति—तीनों की परीक्षा बन गया है। आमतौर पर उपचुनाव स्थानीय मुद्दों तक सीमित रहते हैं लेकिन बांकीपुर का चुनाव बिहार की राजनीति में कहीं अधिक व्यापक अर्थ रखता है। राजधानी की यह सीट लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ रही है। इसलिए यहां होने वाला हर चुनाव पूरे राज्य में राजनीतिक संदेश देता है। यही कारण है कि इस बार

चुनावी मुकाबला सामान्य नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। सबसे अधिक चर्चा जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर है। वर्षों तक देश के सबसे चर्चित चुनावी रणनीतिकार बड़े प्रशांत किशोर पहली बार ऐसे चुनाव में हैं, जहां रणनीति बनाने के साथ-साथ स्वयं जनता से वोट भी मांग रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा ने किसी बड़े राजनीतिक चेहरे के बजाय बृथ स्तर से निकले कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाकर यह संदेश दिया है कि उसके लिए संगठन किसी भी व्यक्ति से बड़ा है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारकर राजधानी में अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की है। बांकीपुर केवल राजधानी का विधानसभा क्षेत्र नहीं है। यह बिहार के शिक्षित मध्यमवर्ग, व्यापारी समुदाय, पेशेवर वर्ग और लंबे समय से भाजपा के वैचारिक आधार का प्रतिनिधित्व करने वाली



सीट मानी जाती है। इस सीट पर जीत भाजपा के लिए केवल एक विधायक नहीं जोड़ती, बल्कि यह संदेश देती है कि शहरी बिहार में उसका प्रभाव अब भी कायम है। यही कारण है कि पार्टी ने इस चुनाव में पूरी संगठनात्मक ताकत झोंक दी है। शक्ति केंद्रों से लेकर बृथ समितियों तक सक्रियता बढ़ा दी गई है। घर-घर संपर्क अभियान चल रहा है। वरिष्ठ नेताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। भाजपा की रणनीति साफ है—संगठन, अनुशासन और बृथ प्रबंधन के सहारे चुनाव जीतना।

बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष एवं पूर्व विधान पार्षद प्रो. तारा नंदा जैसे नेताओं का प्रचार में उतरना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। उनका यह दावा कि “बांकीपुर फिर भाजपा के साथ खड़ा होगा” केवल चुनावी नारा नहीं, बल्कि भाजपा के आत्मविश्वास को प्रदर्शित करने का प्रयास है। लेकिन इस व्यापक सक्रियता का दूसरा अर्थ भी है। भाजपा इस चुनाव को हल्के में लेने की स्थिति में नहीं है। यदि पार्टी पूरी तरह निश्चित होती, तो इतनी व्यापक चुनावी तैयारी की आवश्यकता शायद नहीं पड़ती। प्रशांत किशोर लंबे समय तक दूसरों के चुनाव जिताने वाले रणनीतिकार रहे हैं। उन्होंने कई राज्यों में चुनावी अभियान संचालित किए और आधुनिक चुनावी प्रबंधन की नई शैली विकसित की लेकिन राजनीति और चुनाव प्रबंधन दो अलग-अलग विधाएं हैं। रणनीतिकार चुनाव जिता सकता है,

■ साभार

